चीनी उद्योग को अजित का साथ

केंद्रीय मंत्री अजित सिंह ने समस्याओं के हल के लिए प्रधानमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 25 अक्टूबर

आर्थिक संकट से जूझ रही उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) नेता अजित सिंह का समर्थन मिला है। सिंह ने आज संकटग्रस्त चीनी मिलों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की मांग की है। देश के कुल चीनी उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चीनी उत्पादक इलाकों में रालोद का अच्छा प्रभाव है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सिंह ने कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा कर तत्काल कदम उठाए जाने की मांग की है, जिससे चीनी उद्योग चालू रह सके। उन्होंने मांग किया कि केंद्र सरकार 30 लाख टन चीनी निर्यात के लिए प्रोत्साहन की घोषणा करे। भारत में चीनी का अतिरिक्त भंडार होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 'हमें चीनी का निर्यात करने की जरूरत है, न कि ब्राजील और पाकिस्तान से सस्ते आयात करने की। ऐसे में चीनी पर आयात शुल्क तत्काल 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 40-60 प्रतिशत के बीच किया जाना चाहिए।' इसके अलावा सिंह ने चीनी मिलों को 4-5 साल के लिए कर्ज मुहैया कराने हेतु योजना लाने का सुझाव दिया है, जिसके लिए सरकार को सामान्य कोषागार और चीनी विकास निधि से ब्याज की धनराशि मुहैया कराई जानी चाहिए।

सिंह ने मांग किया कि अतिरिक्त चीनी के एक हिस्से को एथेनॉल बनाने के लिए भेजा जाना चाहिए, जिससे 15-20 टन अतिरिक्त चीनी का स्टॉक घटाया जा सके। उन्होंने कहा, 'इससे चीनी मिलों के नकदी का संकट दूर होगा। साथ ही तेल आयात पर खर्च होने वाली देश की विदेशी मुद्रा भी बचाई जा सकेगी और इससे चालू खाता घाटा (सीएडी) कम होगा।'

उन्होंने ध्यान दिलाया कि पेराई का नया सत्र करीब है और अभी भी राज्य की चीनी मिलों पर 2400 करोड़ रुपये गन्ने का बकाया है।

चीनी मिलों की मदद करे सरकार

- अजित सिंह ने प्रधानमंत्री से कैबिनेट की अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर तत्काल कदम उठाने की मांग की
- उन्होंने कहा कि सरकार करीब 30 लाख टन चीनी के निर्यात की घोषणा करे
- उन्होंने चीनी मिलों को 4-5 साल के लिए सस्ता कर्ज मुहैया करने की योजना लाने का भी सुझाव दिया

Business Standard
26/10/13